भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1628
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

प्रधानमंत्री जी-वन योजना के अंतर्गत बजट

†1628. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री जी-वन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में बजट आवंटन 314.36 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 227.26 करोड़ रुपये रह जाने के कारण पेश आ रही अनेक चुनौतियों की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास परियोजना विकासकर्ताओं की उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढने, समय पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से निपटने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करने हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न उन्नत बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की वर्तमान स्थिति क्या है और कार्य आरंभ कर चुकी, निर्माणाधीन एवं अभी तक शुरू नहीं की जा सकीं परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) वे मानदंड क्या हैं जिनके द्वारा बोल्ट-ऑन और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं इस योजना में संगत बैठती हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता निर्धारित परियोजना के लक्ष्यों के सफल समापन के आधार पर जारी की जाती है। प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 314.36 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 227.26 करोड़ रूपये का बजटीय आवंटन परियोजना डेवलपर्स द्वारा की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि आधारित प्रगति के अनुसार धन राशि जारी करने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख): इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने दूसरे पीढ़ी (2जी) इथेनोल उत्पादन के लिए स्वदेशी 2जी इथेनोल तकनीकी विकसित की है। देश में विभिन्न उपकरण निर्माण कंपनियों द्वारा 2जी इथेनोल के उत्पादन के लिए प्राथमिक उपकरण जैसे श्रेडर, वेट-वाशर, प्री-ट्रीटमेंट यूनिट, एंजाईमेटिक हाइड्रोलिसिस यूनिट, फ़र्मेंटर, कॉ-फ़र्मेंटर,

डिस्टिलिकरण/डिहाइड्रेशन कॉलम, बॉयलर आदि निर्माण किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित चुनौतियों, यदि कोई हो, की संबंधित कंपनी एवं सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती हैं तथा मुद्दों का निरंतर आधार पर समाधान किया जाता है।

(ग): प्रधानमंत्री जी-वन योजना के अंतर्गत विभिन्न उन्नत जैव-ईंधन परियोजनाओँ के लिए वित्तीय सहायता की वर्तमान स्थिति तथा चालू, निर्माणाधीन तथा अभी शुरू होने वाली परियोजनाओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**प्रोजेक्ट्स डेवलपर**	**परियोजना प्रकार**	**स्वीकृत वित्तीय सहायता करोड़ रुपए में)**	**वित्तीय सहायता वितरित करोड़ रुपए में)**	**पूरा होने की समय सीमा**
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा	वाणिज्यिक	150	75	कमीशंड
2	भारत ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओडिशा	वाणिज्यिक	150	75	यांत्रिक रूप से पूर्ण
3	हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजाब	वाणिज्यिक	150	37.5	वित्त वर्ष 2025-26
4	नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड, असम	वाणिज्यिक	150	75	यांत्रिक रूप से पूर्ण
5	मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, कर्नाटक	वाणिज्यिक	100	-	अभी शुरू होना बाकी है
6	राइस सेल्यूलोज प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	वाणिज्यिक	150	-	अभी शुरू होना बाकी है
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा	प्रदर्शन	15	-	यांत्रिक रूप से पूर्ण
8	हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार	प्रदर्शन	15	-	निर्माण पूर्व गतिविधि के अंतर्गत
9	लिग्नोपुरा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र	प्रदर्शन	13.25	-	निर्माण-पूर्व गतिविधि के अंतर्गत
10	गोदावरी बायोरिफाइनरीज लिमिटेड, कर्नाटक	प्रदर्शन	15	-	निर्माण-पूर्व गतिविधि के अंतर्गत

(घ): सरकार ने अगस्त 2024 में प्रधान मंत्री जी-वन योजना में संशोधन किया है और इस योजना के तहत बोल्ट ऑन और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया है ताकि मौजूदा संयंत्र के अनुभव और स्थापित बुनियादी ढांचे का लाभ लिया जा सके, पूंजीगत लागत को कम करके परियोजना की व्यवहार्यता मे सुधार किया जा सके और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

****